(b) what is the number of T.V stations opened during the last three years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) A statement containing the norms observed in the matter of setting up of TV Stations is attached.

(b) During the last three years (effective from August 15, 1982), 154 new TV Centres in the country were commissioned.

The criteria for setting up of a TV transmitters include factors such as extent of coverage to rural and urban population; service to backward remote and sensitive border areas; coverage of working class|industrial population; availability of programme production and programme linking facilities and other infrastructure. The needs of places of cultural, historical and industrial importance are also taken into account. Efforts are also made to give priority to areas which are not yet covered by TV signals. While choosing the site for a particular transmitter, the peculiarities of the local terrain are also considered so as to maximise the area that will be covered by the transmitter. This is further subject to availability of resources and relative priorities.

राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना

1643. **श्री भंवर लाल पंवार** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या जालोर-सिरोही में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र खोला गया है ; यदि नहीं, तो इसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार जोधपुर में एक कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के कारण ये है (क) राज्य के पिछड़े जिलों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण सम्बन्धी अवस्थापन सुविधाओं का विकास; और (ख) कृषकों, कृषि महिलाओं, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों तथा राज्य के कृषि विभाग के क्षेत्र स्तर के विस्तार कर्मचारियों को दक्षतापरक प्रशिक्षण देना :

(ख) 1984-85 के उत्तरार्द्ध में जालौर में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई थी । सिरोही में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किया जा सकता है ।

(ग) कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय आदेश जारी करता है । इसलिए, जोधपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का है, यदि राजस्थान में कृषि से संबंधित मानव शक्ति की कमी है ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये राजस्थान को निधियों का आवंटन

1644. **श्री भंवर लाल पंवार** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई सहायता और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई और पूरी राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) 1985-86 के वर्ष के दौरान इस मद में कितनी राशि दिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। राज्य सरकार केवल मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ही उन्हें मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं कर पाई थी। राज्य सरकार मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना बराबर का अंश नहीं दे सकी थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग कम था क्योंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 1983-84 में काफी देर से प्रारम्भ हुआ था

विवरण

(क) इस मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा वंटित निधियां :

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम	1982-83	1983-84	1984-85
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम . .	176.17	194.23	206.96
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम . .	199.61	187.76	231.21
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम .	—	100.00	399.97
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम . .	28.17	33.37	34.62
मरुभूमि विकास कार्यक्रम . . .	6.85	9.00	10.08

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों का केन्द्रीय वंटन :

निधियों का केन्द्रीय बंटन* :

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	1982-83	1983-84	1984-85	राज्य अंश सहित कुल व्यय 1982-83	1983-84	1984-85
स०ग्रा०वि०का०	983.00	1053.00	974.00	2196.00	2020.69	2052.49
रा०ग्रा०रो०का०	457.55	488.65	775.00	854.48	1040.07	1686.21
ग्रा०भू०रो०गा०का०	—	240.00	1212.00	—	50.54	970.12
सूखा सं० क्षेत्र का०	96.67	64.86	134.72	665.59	212.92	189.45
म० वि०का०	461.83	652.62	756.26	688.55	954.68	1017.15

*ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी धनराशि दी जाती है, को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा बराबर की धनराशि देनी पड़ती है।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अखिल भारतीय तथा राजस्थान हेतु निधियों का केन्द्रीय आवंटन :

(लाख रुपयों में)

	अखिल भारत	राजस्थान
स० ग्रा० वि० का०	20593.42	793.82
रा० ग्रा० रो० का०	23000.00	550.00
ग्रा० भू० रो० गा० का०	49400.00	931.00
सू० संभा० क्षेत्र का०	3690.00	180.00
रु० विकास का०	800.00	548.00

फसल बीमा योजना के अधीन फसलें

1645. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फसलों के नाम क्या-क्या हैं जिनका फसल बीमा योजना के अधीन बीमा किया जा सकता है ;

(ख) सरकार ने योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या कपास, गन्ना और तम्बाकू की फसलों को इस योजना में शामिल किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कुछ आवेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय ले लिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) मौजूदा वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत धान, गेहूं, कदन्न, दलहन और तिलहन का बीमा किया जाता है ।

(ख) 1 मई, 1985 को क्रियान्वयन तरीकों पर राज्यों के कृषि और सहकारिता विभागों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और 17 जुलाई, 1985 को एक समीक्षा बैठक की गई थी । राज्य सरकारों को योजना को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये है । अभी तक 16 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने खरीफ 1985 से योजना को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की है ।

(ग) इस योजना में कपास, गन्ना और तम्बाकू को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने फसल बीमा योजना में कपास को शामिल करने का सुझाव दिया है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस योजना में गन्ना तथा आलू को शामिल करने का सुझाव दिया है ।

(ङ) जी, नहीं ।

Opening of Central pathological laboratory for ESI group of Hospitals in West Bengal

1646. SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER:
SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY:

Will the Minister of LABOUR be *pleased to state:*

(a) whether Government have received any representation on the 22nd